जरनैल सिंह

बनाम

हरियाणा राज्य

(आपराधिक अपील सं. 1209/2010)

1 जुलाई, 2013

[पी. सतशिवम और जगदीश सिंह खेहर, जे. जे.]

दंड संहिता, 1860-एस. एस.366, 376(छ) और 120-8-ए/लीगेशन कि अभियोजन पक्ष को जबरन ले जाया गया था, और अपीलकर्ता और उसके तीन सहयोगियों द्वारा बलात्कार किया गया था-अपीलकर्ता की दोषसिद्धि-औचित्य-आयोजितःअभियोजक उल के बयान को देखते हुए उचित ठहराया गया। 164 सी. आर. पी. सी. के रूप में, निचली निचली अदालत के समक्ष उसके द्वारा दिया गया बयान, और जिस तरह से उससे जिरह की गई थी-अपीलकर्ता के अपराध के स्पष्ट निर्धारण के लिए अभियोजक के बयान की पुष्टि करने वाली पर्याप्त सामग्री-अभियोजक को अपीलकर्ता की हिरासत से बरामद किया गया था और उसके बाद, पी. डब्ल्यू. 1-पी. डब्ल्यू. 1 द्वारा चिकित्सकीय-कानूनी जांच के अधीन, उसकी स्वतंत्र गवाही में पुष्टि की गई थी कि उसे यौन संभोग के अधीन किया गया था, क्योंकि उसका हाइमेन टूट गया था-एफ. एस. एल. और सीरोलॉजिस्ट की रिपोर्ट द्वारा वैज्ञानिक रूप से पुष्टि की गई अभियोजक की गवाही-बचाव याचिका कि अभियोजक ऐप के साथ था। किशोर न्यायाधीश (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) नियम, 2007 -आर. 12-बलात्कार-अभियोजन की आयु-निर्धारण-आयोजितःआर लागू करना उचित और उचित होगा।12 अभियोजक की आयु निर्धारित करने के लिए-भले ही आर।12 केवल कानून के साथ टकराव में एक बच्चे की उम्र निर्धारित करने के लिए सख्ती से लागू होता है, यह उम्र

निर्धारित करने का आधार होना चाहिए, यहां तक कि एक बच्चे के लिए भी जो अपराध का शिकार है-उम्र निर्धारित करने का तरीका निर्णायक रूप से आर के उप-नियम (3) में व्यक्त किया गया है। 12 - आर में प्रतिपादित कई विकल्पों में से पहले उपलब्ध आधार को अपनाकर बच्चे की उम्र का पता लगाया जाता है। 12(3) - सी संबंधित बच्चे का मैट्रिक (या समकक्ष) प्रमाण पत्र, उच्चतम मूल्यांकन विकल्प है-केवल उक्त प्रमाण पत्र की अनुपस्थिति में में,आर. 12 (3) में उस स्कूल में दर्ज जन्म तिथि पर विचार करने की परिकल्पना की गई है जिसमें बच्चा पहली बार उपस्थित हुआ था-ऐसी प्रविष्टि की अनुपस्थिति में में,आर. 12 (3) किसी निगम या नगरपालिका प्राधिकरण या पंचायत द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र पर निर्भरता को अभिनिर्धारित करता है-उपरोक्त में से किसी की अनुपस्थिति में में,आर. 12 (3) चिकित्सा राय के आधार पर संबंधित बच्चे की उम्र के निर्धारण का प्रतिपादन करता है-किशोर न्यायाधीश (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2000-एस।68(1)- दंड संहिता, 1860 -s.376 (जी)।

अभियोजन पक्ष का मामला यह था कि जब अभियोजक सड़क पर पेशाब करने के लिए उसके घर से बाहर गया था, तो अपीलकर्ता और उसके तीन साथियों ने उसका अपहरण कर लिया और उसके बाद उन्होंने एक के बाद एक उसके साथ बलात्कार किया। निचली अदालत ने अपीलकर्ता को भा.दं.सं. की धारा 366,376 (जी) और 120-बी के तहत दोषी ठहराया। इस दोषसिद्धि को उच्च निचली अदालत ने बरकरार रखा।

तत्काल अपील में, अपीलकर्ता द्वारा यह तर्क दिया गया कि अभियोजक ने स्वेच्छा से और अपनी स्वतंत्र सहमति से अपीलकर्ता के साथ यौन संबंध बनाए और इस तर्क के समर्थन में अपीलकर्ता ने बताया कि अभियोजक ने अपीलकर्ता के साथ भागने के लिए अपने पिता के घर से 3,000/- रुपये लिए थे। अपीलकर्ता ने विवादित निर्णय में उच्च न्यायालय के निर्धारण को भी चुनौती दी, जिसमें उसने निष्कर्ष निकाला था कि अभियोजक नाबालिग था।

याचिका खारिज करते हुए न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया

1.1. निचली अदालत के समक्ष अपने बयान में, जहां वह पीडब्लू 6 के रूप में पेश हुई, अभियोजक ने स्पष्ट रूप से अपीलकर्ता और उसके तीन साथियों द्वारा छीन लिए जाने की स्थिति को दोहराया था। उसने पुष्टि की कि उसे एक टैंकर में उत्तर प्रदेश ले जाया गया और फिर सभी अभियुक्तों ने एक छोटे से कमरे में उसके साथ बलात्कार किया। मामले के विवादित पहलू पर, आरोपी के कहने पर उससे जिरह नहीं की गई थी। उसे केवल एक सुझाव दिया गया था कि उसने अपीलकर्ता को उसके साथ शादी आदेशने के लिए उसे ले जाने के लिए राजी किया था और उक्त उद्देश्य के लिए अपने ही आवास से नकदी, कपड़े और गहने ले गई थी। अभियोजक ने वनहीन सुझाव को अस्वीकार कर दिया था। न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी के समक्ष दंड प्रक्रिया संहिता की खंड 164 के तहत अभियोजक के बयान के साथ-साथ निचली निचली अदालत में पेश होने के दौरान उसके द्वारा दिए गए बयान और जिस तरह से उससे जिरह की गई थी, उसे ध्यान में रखते हुए, इस बात में कोई संदेह नहीं है कि अभियोजक को जबरन ले जाया गया था और अपीलकर्ता और उसके तीन साथियों के हाथों उसका बलात्कार किया गया था। यह अभी भी समझ में आ सकता है, अगर मामला था, कि उसने अकेले अपीलकर्ता के साथ सहमति से यौन संबंध बनाए थे।लेकिन एक ही समय में चार लड़कों के साथ सहमति से यौन संबंध बनाना समझ में नहीं आता है। [पैरा 15] [1060-जी ई-एच; 1061-ए-बी]

1.2. अपीलकर्ता द्वारा इस तर्क के संबंध में कि अभियोजक ने 25.3.1993 पर उसके घर से निकलते समय 3,000/- रुपये की राशि ले ली थी, जबकि यह सच है कि शिकायत में, पी. डब्ल्यू. 8, एच. अभियोजक के पिता ने स्पष्ट रूप से उल्लेख किया था कि उनके आवास से 3,000/- रुपये की राशि गायब थी, और उक्त तथ्य का पुलिस को दी गई शिकायत में विधिवत उल्लेख किया गया था, फिर भी उन्होंने अभियोजक पर

इसे ले जाने का आरोप नहीं लगाया था। पी. डब्ल्यू. 8 द्वारा निचली अदालत के समक्ष दिए गए बयान के कारण तत्काल पहलू महत्वहीन हो जाता है कि हालांकि उन्होंने उल्लेख किया था कि उनके आवास से 3,000/- रुपये की राशि गायब थी, लेकिन उनकी पत्नी को कुछ दिनों बाद आवास से ही उपरोक्त धन मिला था। तदनुसार, अपीलकर्ता द्वारा इस प्रभाव से किया गया दावा कि अभियोजक ने 3,000/- रुपये की राशि ले ली थी, जब वह 25.3.1993 पर अपने पिता के घर से निकली थी, को विधिवत साबित नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा, अभियोजक की जिरह से यह स्पष्ट है कि उसे एक सुझाव दिया गया था कि नकदी के अलावा, उसने 25.3.1993 पर अपने पिता के घर से निकलते समय कपड़े और गहने ले लिए थे। अभियोजक ने इस सुझाव को स्पष्ट रूप से अस्वीकार कर दिया।उक्त आरोप की पुष्टि करने के लिए मामले के रिकॉर्ड में कोई सामग्री नहीं है। इसलिए, अभियोजक के खिलाफ अपीलकर्ता द्वारा लगाए गए आरोप को प्रतिग्रहण करना करना संभव नहीं है, या तो अपने घर से निकलते समय 3,000/- रुपये की राशि ले जाने के मुद्दे पर, या कि वह कपड़े और आभूषणों के साथ 25.3.1993 पर अपना घर छोड़ गई थी। तदनुसार, उक्त तथ्यात्मक स्थिति को सत्य मानते हुए जो निष्कर्ष निकाला गया है, वह बस उत्पन्न नहीं होता है। [पैरा 16) [1061-डी-एच; 1062-ए-सी]

2.1. इसके अलावा, अभियोजक घटना की तारीख एफ पर नाबालिग था। भले ही वह अपनी स्वतंत्र इच्छा से अपीलकर्ता के साथ होती, और उसके साथ सहमति से यौन संबंध रखती, लेकिन यह स्पष्ट रूप से अप्रासंगिक होता, क्योंकि वह नाबालिग थी। नाबालिग की आयु निर्धारित करने के मुद्दे पर, अभियोजक की आयु निर्धारित करने के लिए किशोर न्यायाधीश (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) नियम, 2007 (किशोर न्यायाधीश (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2000 की खंड 68 (1) के तहत बनाया गया) के नियम 12 को लागू करना न्यायाधीशसंगत और उचित होगा।भले

ही नियम 12 केवल कानून के साथ टकराव में एक बच्चे की उम्र निर्धारित करने के लिए सख्ती से लागू होता है, उपरोक्त वैधानिक प्रावधान उम्र निर्धारित करने का आधार होना चाहिए, यहां तक कि एक बच्चे के लिए भी जो अपराध का शिकार है। जहां तक अल्पसंख्यक के मुद्दे का संबंध है, कानून के साथ संघर्ष करने वाले बच्चे और अपराध का शिकार होने वाले बच्चे के बीच शायद ही कोई अंतर है। आयु निर्धारित करने का तरीका नियम 12 के उप-नियम (3) में स्पष्ट रूप से व्यक्त किया गया है।उपरोक्त प्रावधान के तहत, नियम 12 (3) में प्रतिपादित कई विकल्पों में से पहले उपलब्ध आधार को अपनाकर बच्चे की उम्र का पता लगाया जाता है।यदि नियम 12 (3) के तहत विकल्पों की योजना में, एक विकल्प पूर्ववर्ती खंड में व्यक्त किया जाता है, तो इसका प्रभाव बाद के खंड में व्यक्त विकल्प पर हावी होता है। उपलब्ध उच्चतम मूल्यांकन विकल्प, निश्चित रूप से नाबालिग की आयु निर्धारित करेगा।नियम 12 (3) की योजना में, संबंधित बच्चे का मैट्रिक (या समकक्ष) प्रमाण पत्र, उच्चतम मूल्यांकन विकल्प है। यदि उक्त प्रमाण पत्र उपलब्ध है, तो किसी अन्य साक्ष्य पर भरोसा नहीं किया जा सकता है।केवल उक्त प्रमाण पत्र की अनुपस्थिति में में, नियम 12 (3), उस स्कूल में दर्ज की गई जन्म तिथि पर विचार करने की परिकल्पना करता है, जिसमें बच्चा पहली बार उपस्थित हुआ था। यदि जन्म तिथि की ऐसी प्रविष्टि उपलब्ध है, तो उसमें दर्शाई गई जन्म तिथि को अंतिम और निर्णायक माना जा सकता है और किसी अन्य सामग्री पर भरोसा नहीं किया जा सकता है।केवल इस तरह की प्रविष्टि की अनुपस्थिति में में, नियम 12 (3) किसी निगम या नगरपालिका प्राधिकरण या पंचायत द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र पर निर्भरता का प्रतिपादन करता है। फिर भी, यदि ऐसा प्रमाण पत्र उपलब्ध है, तो संबंधित बच्चे की उम्र निर्धारित करने के लिए किसी भी अन्य सामग्री पर विचार नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि उक्त प्रमाण पत्र निश्चित रूप से बच्चे की उम्र निर्धारित करेगा।यह केवल उपरोक्त में से किसी की अनुपस्थिति में में

है कि नियम 12 (3) चिकित्सा राय के आधार पर संबंधित बच्चे की उम्र का निर्धारण करता है।[पारस एच 20,21) [1063-ई; 1065-ई-एच; 1066-ए-ई; 1067-डी-ई]

2.2. तत्काल मामले में, 2007 के नियमों के नियम 12 की योजना का पालन करते हुए, यह स्पष्ट है कि अभियोजक की आयु मैट्रिक (या, समकक्ष) प्रमाण पत्र के आधार पर निर्धारित नहीं की जा सकी क्योंकि उसने खुद को अपदस्थ कर दिया था, कि उसने केवल कक्षा 3 तक ही पढ़ाई की थी, और उसके बाद, उसने अपना स्कूल छोड़ दिया था और घर का काम करना शुरू कर दिया था।अभियोजन पक्ष ने इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, 2007-नियमों के नियम 12 (3) में व्यक्त विकल्पों के क्रम में, अगले उपलब्ध आधार पर, अभियोजक की आयु स्थापित करने का प्रयास किया था।अभियोजन पक्ष ने अभियोजक की उम्र साबित करने के लिए पीडब्लू4 को पेश किया। पीडब्लू4 सरकारी हाई स्कूल के हेडमास्टर थे जहाँ अभियोजक ने कक्षा 3 तक पढ़ाई की थी।पीडब्लू4 ने प्रमाण पत्र प्रदर्शनी-पीजी को साबित कर दिया था, जैसा कि स्कूल के रिकॉर्ड के आधार पर बनाया गया था, जो दर्शाता है कि अभियोजक का जन्म 15.5.1977 पर हुआ था। 2007 के नियमों के नियम 12 (3) के तहत विचार की गई योजना में, किसी अन्य तरीके से आयु निर्धारित करने की अनुमति नहीं है, और निश्चित रूप से बाद के खंड में उल्लिखित विकल्प के आधार पर नहीं। इसलिए, उच्च न्यायालय अभियोजक की आयु स्थापित करने के लिए उपरोक्त आधार पर भरोसा करना पूरी तरह से उचित था।इसके अलावा, 2007 के नियमों के नियम 12 की योजना के तहत, उच्च न्यायालय के लिए अभियोजक की आयु निर्धारित करने के लिए अस्थिकरण परीक्षण सहित किसी अन्य सामग्री पर भरोसा करना अनुचित होता। पीडब्लू4 के बयान का विरोध नहीं किया गया है। इसलिए, अभियोजक की जन्म तिथि (प्रदर्शनी पी. जी. में इंगित, 15.7.1977 के रूप में) अंतिमता मानती है।तदनुसार यह

स्पष्ट है कि अभियोजक घटना की तारीख को 15 वर्ष से कम उम्र का था, अर्थात 25.3.1993 पर। [पैरा 21] [1066-ई-एच; 1067-ए-डी]

3. अभियोजन पक्ष का बयान पूरी तरह से अभियोजक के बयान पर आधारित नहीं है। 25.3.1993 पर अपने पिता के आवास से लापता पाए जाने के बाद, और उसके पिता पीडब्लू8 द्वारा 27.3.1993 पर पुलिस में शिकायत करने के बाद, उसे अपीलकर्ता की हिरासत से बरामद कर लिया गया।इसके बाद, अभियोजक को पीडब्लू1 द्वारा दोपहर 3 बजे पीडब्लू1 पर ही मेडिको-लीगल जांच के अधीन किया गया था। पीडब्लू1 ने अपनी स्वतंत्र गवाही में पुष्टि की कि उसे यौन संभोग के अधीन किया गया था, जितना कि उसका हाइमेन टूटा हुआ था। भले ही अभियोजक की दृश्य परीक्षा, उसकी चिकित्सा-कानूनी परीक्षा के दौरान वीर्य या रक्त की उपस्थिति का खुलासा नहीं करती थी, फिर भी फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला (प्रदर्शनी पी. एल.) और सीरोलॉजिस्ट (प्रदर्शनी पी. एल./1) की रिपोर्ट स्पष्ट रूप से उसके सलवार, अंडरवियर और प्यूबिक बालों पर वीर्य की उपस्थिति स्थापित करती है। सीरोलॉजिस्ट की रिपोर्ट से उनके "सलवार" पर मध्यम और छोटे रक्त के धब्बों का भी पता चलता है।अपने स्वयं के बयान में, उसने उल्लेख किया था कि जब अपीलकर्ता और उसके सहयोगियों द्वारा उसका बलात्कार किया गया था, तो खून बह रहा था और उसे दर्द महसूस हो रहा था, और उसके कपड़े खून से सना हुए थे। उनके बयान को प्रदर्शनी पी. एल. और पी. यू. 1 द्वारा वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित किया गया है।अपीलकर्ता के कहने पर, उसकी प्रतिपरीक्षा के दौरान, अभियोजक को दिया गया यह सुझाव कि वह अपनी स्वतंत्र इच्छा से अपीलकर्ता के साथ थी और उसने सहमति से उसके साथ यौन संबंध बनाए थे, किसी भी संदेह के लिए कोई जगह नहीं छोड़ता है कि वह उसके साथ थी और उसने उसके साथ यौन संबंध बनाए थे। यह दावा कि अभियोजक अपीलकर्ता के साथ था, और उसके साथ सहमति से यौन संबंध बनाए थे, पूरी तरह से खारिज कर दिया गया है, क्योंकि

प्रमाणित अभियोजन संस्करण के अनुसार, अभियोजक को केवल अपीलकर्ता द्वारा ही नहीं, बल्कि उसके तीन सहयोगियों द्वारा भी ले जाया गया था।उन चारों ने समान रूप से उसके व्यक्तित्व का उल्लंघन किया था।इसके अतिरिक्त, दंड प्रक्रिया संहिता की खंड 164 के तहत अपने बयान में, अभियोजक ने जोर देकर कहा था कि पहली बार में, उसे पकड़ने के बाद, आरोपी ने उसे एक कपड़े से कुछ सांस ली थी जिससे वह बेहोश हो गई थी।इसके बाद, जब अपीलकर्ता ने उसके साथ संभोग करने का प्रयास किया, तो उसने उसे थप्पड़ मार दिया था।फिर उसने उसके मुँह में एक कपड़ा डाल दिया था, ताकि वह उसे शोर मचाने से रोक सके। इसके बाद, प्रत्येक साथी ने बारी-बारी से उसके साथ जबरन यौन संबंध बनाए।अपीलकर्ता और उसके सहयोगियों द्वारा जबरन संभोग करने के तथ्य को उसने निचली अदालत के समक्ष पी. डब्ल्यू. 6 के रूप में अपनी गवाही के दौरान दोहराया था। उपरोक्त के अलावा, उसके अपने पिता पीडब्लू8 का एक बयान है, जिन्होंने भौतिक विवरणों में भी अभियोजक की गवाही की पुष्टि की थी।अभियोजक से इनमें से किसी भी मुद्दे पर जिरह नहीं की गई थी।न ही अभियोजक को दंड प्रक्रिया संहिता की खंड 161 या खंड 164 के तहत उसके द्वारा दिए गए बयानों का सामना करना पड़ा, ताकि वह विसंगतियों, यदि कोई हो, को समझाने में सक्षम हो सके। इसलिए, अपीलकर्ता के डी अपराध के स्पष्ट निर्धारण के लिए अभियोजक के बयान की पुष्टि करने वाली पर्याप्त सामग्री थी।[पैरा 24] [1068-सी, डी-एच; 1069-ए-एच; 1070-ए]

आपराधिक अधिकार क्षेत्र न्यायनिर्णयःदाण्डिक अपीलीय संः1209/2010

पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय चंडीगढ़ के दाण्डिक अपीलीय सं 247-एस. बी./1995 के निर्णय और आदेश में दिनांक 04.11.2008 से।

एच. पी. एसःईशर, डॉ. कैलाश चंद अपीलकर्ता की ओर से।

मीरा भाटिया, कमल मोहन गुप्ता उत्तरदाता के लिए।

न्यायालय का निर्णय जगदीश सिंह खेहर, जे. द्वारा सुनाया गया।

1. जिस तथ्यात्मक स्थिति पर अभियोजन पक्ष का बयान आधारित है, वह सावित्री देवी (अभियोजक वी. डब्ल्यू.-पी. डब्ल्यू. 6 की मां) द्वारा अपने पति जगदीश चंदर-पी. डब्ल्यू. 8 को सुबह लगभग 6 बजे जानकारी देने के साथ शुरू होती है।उसने अपने पति को सूचित किया कि अभियोजक वी. डब्ल्यू.-पी. डब्ल्यू. 6 उनके आवास से लापता है।इस संबंध में यह उल्लेख करना उचित होगा कि आईडी1 पर रात करीब 10 बजे जगदीश चंदर अपने आवास के बैठक (बैठक कक्ष) में सोने गए थे।अभियोजक बनाम पीडब्लू-6 की माँ सावित्री देवी, अभियोजक बनाम पीडब्लू-6 और अन्य बच्चों (जिसमें तीन बेटे, अभियोजक बनाम पीडब्लू-6 और एक अन्य बेटी शामिल थे) के साथ घर के अन्य कमरों में बी सोने चली गईं।सावित्री देवी ने अपने पति से कहा कि उन्हें संदेह है कि आरोपी अपीलार्थी जरनैल सिंह उनकी बेटी को ले जाने के लिए जिम्मेदार हो सकता है।

2. जगदीश चंदर-पीडब्लू8 ने अपनी बेटी की तलाश शुरू कर दी।उपरोक्त तलाशी के दौरान, सी आरोपी-अपीलार्थी जरनैल सिंह, जिसका पड़ोस (जगदीश चंदर-पीडब्लू8 का) में निवास था, भी अपने आवास से लापता पाया गया।उसके पिता द्वारा अभियोजक वी. डब्ल्यू.-पी. डब्ल्यू. 6 की खोज व्यर्थ साबित हुई।इसलिए जगदीश चंदर-पीडब्लू8 ने 27.3.1993 पर डी. उप-निरीक्षक प्रभारी, पुलिस चौकी, जथलाना को शिकायत दर्ज कराई।अपनी शिकायत में उन्होंने वी. डब्ल्यू.-पी. डब्ल्यू. 6 को अपनी दो बेटियों में बड़ा बताया।उन्होंने उसकी उम्र लगभग 16 वर्ष बताई।उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि उनकी बेटी वी. डब्ल्यू.-पी. डब्ल्यू. 6 25 और 26 मार्च, ई. 1993 की दरम्यानी रात को उनके आवास से लापता हो गई थी।उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि उनके घर से

3,000/- रुपये की राशि गायब थी, जिसे उन्होंने घर से बाहर निकलते समय उनकी बेटी वीडब्ल्यू-पीडब्लू6 द्वारा ले जाया गया होगा।शिकायत प्रदर्शनी पी. ओ. में, आरोपी-अपीलार्थी जरनैल सिंह की ओर संदेह की सुई की ओर इशारा किया गया था।

3. जगदीश चंदर-पीडब्लू8 की शिकायत दर्ज होने के बाद, अभियोजक वीडब्ल्यू-पीडब्लू6 को जी हरिद्वार जिले के रायपुर में शशि भान के घर से आरोपी-अपीलार्थी जरनैल सिंह की हिरासत से 29.3.1983 पर बरामद किया गया था।अभियुक्त-अपीलार्थी को एक साथ 29.3.1993 पर गिरफ्तार किया गया।

4. अभियोजक वी. डब्ल्यू.-पी. डब्ल्यू. 6 का बयान आपराधिक प्रक्रिया संहिता की खंड 164 के तहत ओ. पी. वर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, जगाधरी एच के समक्ष 6.4.1993 पर दर्ज किया गया था।इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में दंड प्रक्रिया संहिता की खंड 164 के तहत दर्ज उनके संक्षिप्त बयान को यहाँ निकालना आवश्यक है, जिसे यहाँ पुनः प्रस्तुत किया जा रहा हैः

> "उन्होंने कहा कि 25.3.1993 की रात करीब 11 बजे मैं प्रकृति के आह्वान का जवाब देने के लिए अपने घर के पास एक सड़क पर गया। आरोपी जरनैल सिंह और उसके तीन साथी वहाँ छिपे हुए थे।जब मैं प्रकृति की पुकार का जवाब देते हुए उठा तो उन्होंने मुझे पकड़ लिया और कपड़े से कुछ सांस ली, जिससे मैं बेहोश हो गया। वे मुझे किसी वाहन में बिठाकर उत्तर प्रदेश में किसी अज्ञात स्थान पर ले गए। वहाँ वे मुझे एक कमरे में ले गए।
>
> जरनैल सिंह ने मेरे साथ जबरदस्ती गलत (संभोग) किया।मैंने उसके चेहरे पर थप्पड़ मारा, फिर उसने मेरे मुंह में कपड़ा डाल दिया। इसलिए, मैं शोर नहीं उठा सका।इसके बाद, सभी ने बारी-बारी से मेरे

साथ जबरन संभोग किया।मेरी योनि से विशाल डी रक्त निकला, और मुझे बहुत दर्द महसूस हुआ।इसके बाद पुलिस ने हमें पकड़ लिया और मुझे मेरे माता-पिता को सौंप दिया।

5. जाँच पूरी होने पर भारतीय दंड संहिता की धारा 366,376 और 120 के तहत चालान पेश किया गया। यह मामला सत्र न्यायालय, जगाधरी को सौंपा गया था, जिसके बाद इसे अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, जगाधरी को भेजा गया था।अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, जगाधरी ने 20.12.1993 पर आरोप तय किए।अभियुक्त-अपीलार्थी ने दोषी नहीं होने का अनुरोध किया और मुकदमे का दावा किया।

6. अभियुक्त-अपीलार्थी के खिलाफ लगाए गए आरोपों को घर लाने के आदेश अभियोजन पक्ष ने 9 गवाहों से पूछताछ की। इसके बाद अभियोजन पक्ष के साक्ष्य को बंद कर दिया गया। अभियुक्त-अपीलार्थी जरनैल सिंह का बयान तब दंड प्रक्रिया संहिता की खंड 313 के तहत दर्ज किया गया था।उन्होंने अपने खिलाफ लगाए गए आरोपों से इनकार किया और गलत निहितार्थ का अनुरोध किया।उसे अवसर दिए जाने के बावजूद, अभियुक्त-अपीलार्थी ने अपने बचाव में कोई सबूत नहीं दिया।

7. यह दर्ज करना आवश्यक है कि मुकदमे की समाप्ति पर, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, जगाधरी इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि अभियोजन पक्ष भारतीय दंड संहिता की धारा 366,376 (जी) और 120-बी के तहत आरोपी-अपीलार्थी के अपराध को किसी भी संदेह की छाया से परे घर लाने में समर्थ था। अभियुक्त-अपीलार्थी जरनैल सिंह को तदनुसार उसके खिलाफ लगाए गए आरोपों का दोषी ठहराया गया।अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, जगाधरी ने अभियुक्त-अपीलार्थी जरनैल सिंह को सजा के सवाल पर सुनवाई का अवसर दिया।इसके बाद, भारतीय दंड संहिता की खंड 376 (जी) के तहत अपराध के लिए अभियुक्त-अपीलार्थी को 10 साल के लिए कठोर कारावास की सजा सुनाई गई

थी, उसे रू.200 का जुर्माना भी देना था-(जुर्माने के भुगतान में चूक के मामले में, अभियुक्त-अपीलार्थी को 3 महीने के लिए और कठोर कारावास से गुजरना था)।भारतीय दंड संहिता की खंड 366 के तहत अपराध के लिए, अभियुक्त-अपीलार्थी को 7 साल के लिए कठोर कारावास की सजा सुनाई गई थी, और उसे रू.150 का जुर्माना देना था-(जुर्माने के भुगतान में चूक के मामले में, अभियुक्त-अपीलार्थी को 3 महीने के लिए और कठोर कारावास से गुजरना था)।और भारतीय दंड संहिता की खंड 120-बी के तहत अपराध के लिए, अभियुक्त-अपीलार्थी को 7 साल के लिए कठोर कारावास की सजा सुनाई गई थी, और उसे रू.150 का जुर्माना देना था-(जुर्माने के भुगतान में चूक के मामले में, अभियुक्त-अपीलार्थी को 3 महीने के लिए और कठोर कारावास से गुजरना था)।उपरोक्त सजाओं को एक साथ चलाने का आदेश दिया गया था।

8. निचली अदालत द्वारा दिए गए दिनांकित 14.3.1995 के फैसले से असंतुष्ट, अभियुक्त-अपीलार्थी जरनैल सिंह ने दाण्डिक अपीलीय सं. चंडीगढ़ में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के समक्ष 1995 का 247-एस. बी. (इसके बाद उच्च न्यायालय के रूप में संदर्भित)।उच्च न्यायालय ने 4.11.2008 पर अभियुक्त-अपीलार्थी द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया। दोषसिद्धि का निर्णय दिनांक 14.3.1995 और सजा का आदेश दिनांक 15.3.1995 (निचली अदालत यानी अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, जगाधरी द्वारा दिया गया) को बरकरार रखा गया।

9. निचली अदालत के दिनांक आई. डी. 2 और अपीलीय अदालत के दिनांक 14.3.1995 के फैसले से असंतुष्ट, अभियुक्त-अपीलार्थी जरनैल सिंह ने इस अदालत का दरवाजा खटखटाया। 7.7.2010 पर, इस न्यायालय ने अपील करने के लिए विशेष अनुमति याचिका (सी. आर. एल.) में अनुमति प्रदान की। नहीं। अभियुक्त अपीलकर्ता द्वारा दायर 2009 का 7836। उपरोक्त मार्ग को पार करने के बाद, तत्काल दाण्डिक अपीलीय अंततः निर्णय के लिए हमारे सामने रखी गई है।

10. अभियुक्त-अपीलार्थी जरनैल सिंह के विद्वान अधिवक्ता के हाथों प्रचार किए गए मुद्दों से निपटने से पहले, संबंधित अभियोजन पक्ष के गवाहों का पक्षपाती दृष्टिकोण रखना समीचीन माना जाता है। इसलिए, हम अभियोजन पक्ष के कुछ गवाहों की गवाही पर विचार करने का प्रयास करेंगेः

(i) डॉ. कांता धनखड़ को अभियोजन पक्ष द्वारा पीडब्लू1 के रूप में पेश किया गया था। उसने दोपहर 3 बजे 29.3.1993 पर अभियोजक वीडब्ल्यू -पीडब्ल्यू6 की चिकित्सकीय-कानूनी जांच की थी। उसकी गवाही के अनुसार, अभियोजक वी. डब्ल्यू.-ई. पी. डब्ल्यू. 6 की जांच के दौरान नग्न आंखों को कोई खून या वीर्य का दाग दिखाई नहीं दे रहा था।प्यूबिक बाल मौजूद थे। बाहरी जननांग या योनि पर कोई दृश्यमान चोट नहीं थी। अभियोजक वी. डब्ल्यू.-पी. डब्ल्यू. 6 का हाइमेन टूटा हुआ पाया गया।उसकी योनि में दो तिहाई उंगलियाँ आसानी से प्रवेश कर जाती थीं।अभियोजक वी. डब्ल्यू.-पी. डब्ल्यू. 6 के कपड़े, उसकी योनि और उसके गुप्तांग के बालों से लिया गया एक स्वाब, जांच के लिए फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला में भेजा गया था, ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि उस पर कोई वीर्य या रक्त था या नहीं।डॉ. कांता धनखड़-पीडब्लू1 की गवाही के साथ, यह दर्ज करना आवश्यक है कि फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला (प्रदर्शनी पीएल) की रिपोर्ट के अनुसार, अभियोजक के "सलवार" (महिला पतलून), उसके अंडरवियर और उसके गुप्तांग के बालों पर भी मानव वीर्य का पता चला था। सीरोलॉजिस्ट (प्रदर्शनी पी. एल./1) की रिपोर्ट में आगे "सलवार" पर मध्यम और छोटे आकार के रक्त के धब्बों का पता चला।सीरोलॉजिस्ट की रिपोर्ट से यह भी पता चला कि "सलवार" पर दाग मानव रक्त के थे।

(ii) डॉ. सतनाम सिंह-पीडब्लू2, अभियोजन पक्ष द्वारा जाँच किए जाने वाले दूसरे गवाह थे। उन्होंने अभियुक्त-अपीलार्थी जरनैल सिंह की चिकित्सकीय-कानूनी जांच कराई थी।

डॉ. सतनाम सिंह-पीडब्लू2 ने निचली अदालत के समक्ष गवाही देते हुए पुष्टि की कि अभियुक्त-अपीलार्थी यौन संभोग करने में सक्षम था।

(iii) अभियोजन पक्ष ने मोती राम से पी. डब्ल्यू. 3 के रूप में पूछताछ की।मोती राम ने गवाही दी कि वह उस समय मौजूद था जब अभियोजक वी. डब्ल्यू.-पी. डब्ल्यू. 6, हरिद्वार जिले के रायपुर में शशि भान के घर से आरोपी-अपीलार्थी की हिरासत में बरामद किया गया था।मोती राम ने 29.3.1993 पर अभियोजक वी. डब्ल्यू.-पी. डब्ल्यू. 6, की बरामदगी के समय पुलिस दल के साथ ओम प्रकाश, जागरणल और सुमेर चंद की उपस्थिति की भी पुष्टि की। मोती राम ने अपनी कथित बरामदगी के समय अभियोजक वी. डब्ल्यू.-पी. डब्ल्यू. 6 की पहचान की थी।

(iv) सतपाल को अभियोजन पक्ष ने अपने चौथे गवाह के रूप में पेश किया था। सतपाल-पीडब्लू4 एफ गवर्नमेंट हाई स्कूल, जथलाना के हेडमास्टर थे, यानी जिस स्कूल में अभियोजक वीडब्ल्यू-पीडब्लू6 ने पहली बार पढ़ाई की थी। सतपाल-पीडब्लू4 ने प्रमाण पत्र एग्ज़िबिट पीजी को साबित किया, जो स्कूल के रिकॉर्ड के आधार पर तैयार किया गया था। प्रमाण पत्र, प्रदर्शनी पी4 के अनुसार, अभियोजक वीडब्ल्यू-पीडब्लू6 का जन्म 15.5.1977 पर हुआ था।

(v) अभियोजक निचली अदालत के समक्ष पीडब्लू 6 के रूप में पेश हुआ।उन्होंने अपने पिता जगदीश चंदर-पीडब्लू8 द्वारा अपनी शिकायत दिनांक 27.3.1993 (प्रदर्शनी पीओ) में व्यक्त की गई तथ्यात्मक स्थिति की पुष्टि की। उन्होंने 6.4.1993 पर दंड प्रक्रिया संहिता की खंड 164 के तहत दर्ज अपने बयान में व्यक्त की गई तथ्यात्मक स्थिति को भी दोहराया। संक्षेप में उन्होंने कहा कि उन्होंने सरकारी हाई स्कूल, जथलाना में कक्षा 3 तक पढ़ाई की थी, जिसके बाद उन्होंने घर का काम करना शुरू कर दिया।आई. डी. 1 को रात करीब 11 बजे वह सड़क पर पेशाब करने के लिए अपने घर से बाहर गई थी।

अभियुक्त-अपीलार्थी जरनैल सिंह और तीन अन्य व्यक्तियों ने उसे पकड़ लिया था और उसे उत्तर प्रदेश में रायपुर की ओर एक टैंकर में ले गए थे। अभियुक्त-अपीलार्थी जरनैल सिंह और उसके तीन साथियों ने एक छोटे से कमरे में उसके साथ बलात्कार किया था। उसने यह भी गवाही दी कि उसे पुलिस ने रायपुर से बरामद किया था, और उसकी बरामदगी के समय, मोती राम-पीडब्लू 3 और उसके चाचा ओमीलाल (ओम प्रकाश) और जगमल पुलिस दल के साथ मौजूद थे। इसके बाद, उसका दावा है कि उसे जथलाना पुलिस चौकी लाया गया था, और सिविल अस्पताल, रादौर में एक महिला डॉक्टर द्वारा उसकी चिकित्सकीय-कानूनी जांच कराई गई थी। चूंकि अभियोजक वी. डब्ल्यू.-पी. डब्ल्यू. 6, पूरी तथ्यात्मक स्थिति का खुलासा नहीं कर रहा था, और आपराधिक प्रक्रिया संहिता की खंड 164 के तहत दर्ज उसके बयान के संस्करण को बदल रहा था, इसलिए लोक अभियोजक ने उससे जिरह करने की अनुमति मांगी। अभियोजक वी. डब्ल्यू.-पी. डब्ल्यू. 6 को क्रॉसएक्सामाइन करने की अनुमति दिए जाने के परिणामस्वरूप, उसने पुष्टि की कि आरोपी-अपीलकर्ता उसे शादी के लिए लुभा रहा था, उसे गहने और कपड़े देने के वादे के साथ, और उनकी शादी के बाद उसे शहर में स्थानांतरित करने की प्रतिबद्धता के साथ।इन प्रलोभनों के दौरान, आरोपी-अपीलकर्ता जरनैल सिंह भी उसमर्थ यह समझाता था कि उसके माता-पिता गरीब हैं और वह उसकी शादी किसी गरीब व्यक्ति समर्थ कर देगा, जो उसमर्थ कभी भी ऐसी सुविधाएं प्रदान नहीं कर पाएगा।अपनी जिरह के दौरान, उसने स्पष्ट रूप से इस सुझाव का खंडन किया कि उसने खुद आरोपी-अपीलआदेश्ता जरनैल सिंह को उससे शादी आदेशने के लिए उसे ले जाने का प्रलोभन दिया था।

(vi) ओ. पी. वर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, जगाधरी, पीडब्लू 7 के रूप में उपस्थित हुए।अभियोजक वी. डब्ल्यू.-पी. डब्ल्यू. 6 द्वारा आपराधिक प्रक्रिया संहिता की

खंड 164 के तहत उनके समक्ष दर्ज किए गए बयान को उन्होंने 6.4.1993 पर साबित किया।

(vii) अभियोजक वी. डब्ल्यू.-पी. डब्ल्यू. 6 के पिता जगदीश चंदर-पी. डब्ल्यू. 8 ने अपने बयान के दौरान, सी ने 27 तारीख की अपनी शिकायत में दर्शाए गए तथ्यात्मक स्थिति की पुष्टि की।उन्होंने सभी भौतिक विवरणों में अपनी बेटी (यानी अभियोजक वी. डब्ल्यू.-पी. डब्ल्यू. 6) की गवाही की भी पुष्टि की।

अभियुक्त-अपीलार्थी को निचली अदालत (14.3.1995 पर) और उच्च न्यायालय (4.11.2008 पर) के हाथों दोषसिद्धि मुख्य रूप से अभियोजन पक्ष के गवाहों के बयानों पर आधारित थी जिनका सारांश ऊपर दिया गया था।

11. अब हम अभियुक्त अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता के हाथों दिए गए प्रस्तुतिकरणों पर विचार करने का प्रयास करेंगे।

12. अभियुक्त-अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता के हाथों पहला और सबसे महत्वपूर्ण तर्क यह था कि अभियोजक वी. डब्ल्यू.-पी. डब्ल्यू. 6, स्वेच्छा से और उसकी स्वतंत्र सहमति से, अभियुक्त-अपीलार्थी जरनैल सिंह के साथ था। यह तर्क दिया गया कि वास्तव में, यह अभियोजक वी. डब्ल्यू.-पी. डब्ल्यू. 6 ही था जिसने आरोपी-अपीलार्थी को उससे शादी करने के लिए लुभाया था, और उसे जी. 25 और 26 मार्च, 1993 की दरम्यानी रात के दौरान उसे ले जाने के लिए राजी किया था।तत्काल निवेदन की पुष्टि आदेशने के लिए, यह बताया गया कि अभियोजक वी. डब्ल्यू.-पी. डब्ल्यू. 6 बिना किसी विरोध के आरोपी जरनैल सिंह के साथ चार दिनों तक रहा है। अभियुक्त-अपीलार्थी जरनैल सिंह, एच के साथ उपरोक्त चार दिनों के दौरान वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर गए थे और अंत में रायपुर में शशि भान के घर पहुंचे थे (जहाँ से पुलिस ने उसे 29.3.1993 पर बरामद किया था)। यह प्रस्तुत किया गया था कि जंगलों से घिरे चार

दिनों के दौरान अलार्म बजाने के लिए उसके पास पर्याप्त अवसर था।तथ्य यह है कि उसने कोई चेतावनी नहीं दी, यह दर्शाता है कि वह स्वेच्छा से आरोपी अपीलार्थी जरनैल सिंह के साथ रही थी।इसलिए, विद्वान अधिवक्ता के अनुसार, आरोपी-अपीलकर्ता जरनैल सिंह के साथ यौन संबंध भी सहमति से किया गया था। इस प्रकार यह देखा गया कि अभियुक्त-अपीलार्थी जरनैल सिंह पर न तो उसका अपहरण करने और/न ही उसके साथ बलात्कार करने का आरोप लगाया जा सकता है।

13. इसी मुद्दे पर, अभियुक्त-अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने इस तथ्य की ओर भी हमारा ध्यान आकर्षित किया कि जगदीश चंद्र (पीडब्लू8) द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत में, दिनांक आई. डी. 1 में, उन्होंने स्पष्ट रूप से उल्लेख किया था कि अभियोजक ने 3,000/- रुपये की राशि ले ली थी।इस ओर से यह प्रस्तुत किया गया था कि अभियोजक की तत्काल कार्रवाई से पता चलता है कि उसने आरोपी-अपीलार्थी जरनैल सिंह की संगति में भागने के लिए अपने पिता के घर से पैसे लिए थे।उपरोक्त से यह अनुमान लगाने की कोशिश की जाती है कि अभियोजक वी. डब्ल्यू.-पी. डब्ल्यू. 6 अभियुक्त-अपीलार्थी जरनैल सिंह के साथ अपनी मर्जी से गई थी।और, कि उसने सहमति से उसके साथ यौन संबंध बनाए।ऊपर बताए गए कारणों के लिए, यह अभियुक्त अपीलकर्ता जरनैल सिंह के विद्वान अधिवक्ता का जोरदार तर्क था कि नीचे की अदालतों ने भारतीय दंड संहिता की धारा 366,376 और 120-बी के तहत अपीलकर्ता की दोषसिद्धि दर्ज करने में गंभीर त्रुटि की थी।

14. हमने अभियुक्त-अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता के हाथों दिए गए पहले तर्क पर विचारपूर्वक विचार किया है।हम अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा विचार में लिए गए तथ्यात्मक पहलुओं को निर्धारित करने का साहस करेंगे, ताकि अभियोजक वी. डब्ल्यू.-पी. डब्ल्यू. 6 की कथित स्वतंत्र इच्छा और सहमति को व्यक्तिगत रूप से

प्रमाणित किया जा सके, ताकि ऊपर उल्लिखित प्रस्तुतियों की सत्यता को प्रभावी ढंग से निर्धारित किया जा सके।

15. जहाँ तक अभियुक्त अपीलकर्ता जरनैल सिंह के साथ उसकी अपनी स्वतंत्र इच्छा से जाने और उसके साथ सहमति से यौन संबंध बनाने का मुद्दा है, केवल अभियोजक वी. डब्ल्यू.-पी. डब्ल्यू. 6 के निर्विरोध बयान की जांच करना आवश्यक है। इस संबंध में यह इंगित किया जा सकता है।अभियोजक वी. डब्ल्यू.-पी. डब्ल्यू. 6 ने न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, जगाधरी के समक्ष आपराधिक प्रक्रिया संहिता की खंड 164 के तहत दर्ज अपने बयान में स्पष्ट रूप से कहा था कि जब वह सड़क पर पेशाब करने के लिए अपने घर से बाहर गई थी, तो उसे जरनैल सिंह और उसके तीन साथियों द्वारा जबरन 25.3.1993 पर ले जाया गया था। उसने स्पष्ट और स्पष्ट रूप से गवाही दी थी कि चारों ने उसे पकड़ लिया था। उन्होंने उसे कुछ सांस लेने के लिए कहा था, जिससे वह बेहोश हो गई थी। उसने आगे कहा था कि आरोपी-अपीलकर्ता जरनैल सिंह और उसके साथी उसे एक वाहन में उत्तर प्रदेश में किसी अज्ञात स्थान पर ले गए थे, जहाँ जरनैल सिंह ने उसके साथ जबरन यौन संबंध बनाने का प्रयास किया था। उस समय, उसने जरनैल सिंह के चेहरे पर थप्पड़ मारा था, लेकिन उसे वश में आदेशने के लिए, उसने उसके मुंह में एक कपड़ा डाल दिया था ताकि वह उसे शोर मचाने से रोक सके। इसके बाद, आरोपी-अपीलार्थी जरनैल सिंह और उसके साथियों ने एक के बाद एक उसके साथ जबरन यौन संबंध बनाए।निचली अदालत के समक्ष अपने बयान में, जहां वह पीडब्लू 6 के रूप में पेश हुई, उसने स्पष्ट रूप से इस स्थिति को दोहराया था कि आरोपी-अपीलार्थी जरनैल सिंह और उसके तीन साथियों ने उसे छीन लिया था।उसने पुष्टि की कि उसे एक टैंकर में उत्तर प्रदेश ले जाया गया और फिर सभी अभियुक्तों ने एक छोटे से कमरे में उसके साथ बलात्कार किया। मामले के विवादित पहलू पर, आरोपी के कहने पर उससे जिरह नहीं की गई थी। उसे केवल एक सुझाव दिया गया

था कि उसने आरोपी अपीलकर्ता जरनैल सिंह को उसके साथ शादी आदेशने के लिए उसे ले जाने के लिए राजी किया था और उक्त उद्देश्य के लिए अपने ही आवास से नकदी, कपड़े और गहने ले गई थी। अभियोजक वी. डब्ल्यू.-पी. डब्ल्यू. 6 द्वारा वनहीन सुझाव को अस्वीकार कर दिया गया था।न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, जगाधरी के समक्ष दंड प्रक्रिया संहिता की खंड 164 के तहत अभियोजक वी. डब्ल्यू.-पी. डब्ल्यू. 6 के बयान के साथ-साथ निचली निचली अदालत में पेश होने के दौरान उसके द्वारा दिए गए बयान और जिस तरह से उससे जिरह की गई थी, उसे ध्यान में रखते हुए, इस बात में किसी भी संदेह की कोई गुंजाइश नहीं है कि अभियोजक को जबरन ले जाया गया था और आरोपी-अपीलकर्ता जरनैल सिंह और उसके तीन साथियों के हाथों उसका बलात्कार किया गया था। यह अभी भी समझ में आ सकता है, अगर मामला होता, कि उसने अकेले आरोपी अपीलकर्ता के साथ सहमति से यौन संबंध बनाए थे। लेकिन एक ही समय में चार लड़कों के साथ सहमति से यौन संबंध बनाना समझ में नहीं आता है। चूंकि यह तथ्य विवादित नहीं है कि अभियुक्त-अपीलीय जरनैल सिंह और अभियोजक वी. डब्ल्यू.-पी. डब्ल्यू. 6 एक साथ भाग गए थे। और इसके अलावा, क्योंकि अभियुक्त-अपीलार्थी का अभियोजक के साथ यौन संबंध होना भी विवादित है। अभियुक्त अपीलार्थी की ओर से प्रचार किए गए प्रस्ताव को प्रतिग्रहण करना करना संभव नहीं है। इसलिए, हम तत्काल प्रस्तुत करने में कोई योग्यता नहीं पाते हैं।

16. अभियुक्त-अपीलार्थी जरनैल सिंह के विद्वान अधिवक्ता के हाथों यह तर्क दिया गया कि अभियोजक वी. डब्ल्यू.-पी. डब्ल्यू. 6 ने 25.3.1993 पर अपने घर से निकलते समय 3,000/- रुपये की राशि ले ली थी, जिसकी समग्र जांच की आवश्यकता है। हालाँकि यह सच है कि शिकायत में अभियोजक वी. डब्ल्यू.-पी. डब्ल्यू. 6 के पिता जगदीश चंद्र (पी. डब्ल्यू. 8) ने स्पष्ट रूप से उल्लेख किया था कि उनके आवास से 3,000/- रुपये की राशि गायब थी, और उक्त तथ्य का पुलिस को उनकी शिकायत में

विधिवत उल्लेख किया गया था, फिर भी उन्होंने अभियोजक वी. डब्ल्यू.-पी. डब्ल्यू. 6 पर इसे ले जाने का आरोप नहीं लगाया था।जगदीश चंद्र (पीडब्लू8) द्वारा निचली अदालत के समक्ष दिए गए बयान के कारण तत्काल पहलू, हमारे सुविचारित दृष्टिकोण में महत्वहीन हो जाता है।निचली अदालत के समक्ष अपने बयान के दौरान, उन्होंने कहा था कि उन्होंने उल्लेख किया था कि उनके आवास से 3,000/- रुपये की राशि गायब थी, लेकिन उनकी पत्नी सावित्री देवी को कुछ दिनों बाद आवास से ही उपरोक्त धन मिला था। तदनुसार, अभियुक्त-अपीलकर्ता का प्रतिनिधित्व करने विद्वान अधिवक्ता द्वारा इस प्रभाव से किया गया दावा कि अभियोजक वी. डब्ल्यू.-पी. डब्ल्यू. 6 ने 3,000/- रुपये की राशि ले ली थी, जब वह 25.3.1993 पर अपने पिता के घर से निकली थी, यह विधिवत साबित नहीं किया जा सकता है। उपरोक्त के अलावा, अभियोजक वी. डब्ल्यू.-पी. डब्ल्यू. 6 की प्रतिपरीक्षा से यह स्पष्ट है कि उसे एक सुझाव दिया गया था कि नकदी के अलावा, उसने 25.3.1993 पर अपने पिता के घर से निकलते समय कपड़े और गहने ले लिए थे। अभियोजक वी. डब्ल्यू.-पी. डब्ल्यू. 6 ने इस सुझाव को स्पष्ट रूप से अस्वीकार कर दिया।उक्त आरोप की पुष्टि करने के लिए मामले के रिकॉर्ड में कोई सामग्री नहीं है। इसलिए, यह संभव नहीं है कि हम अभियोजक वी. डब्ल्यू.-पी. डब्ल्यू. 6 के खिलाफ अभियुक्त-अपीलार्थी जरनैल सिंह द्वारा लगाए गए आरोप को प्रतिग्रहण करना करें, या तो अपने घर से निकलते समय 3,000/- रुपये की राशि ले जाने के मुद्दे पर, या कि वह कपड़े और आभूषणों के साथ आई. डी. 1 पर अपना घर छोड़ गई थी। तदनुसार, उक्त तथ्यात्मक स्थिति को सही मानते हुए सी द्वारा तैयार किया गया निष्कर्ष, बस उत्पन्न नहीं होता है।

17. अपीलकर्ता के लिए विद्वान अधिवक्ता के हाथों दिए गए पहले विवाद को दूसरे दृष्टिकोण से आसानी से निर्धारित किया जा सकता है। उच्च न्यायालय विवादित आदेश में इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि अभियोजक डब्ल्यू.-पी. डब्ल्यू. 6 25.3.1993 पर

घटना के समय वह नाबालिग थी, और उसने यह निष्कर्ष निकाला था कि भले ही वह अपनी स्वतंत्र सहमति से 25.3.1993 पर आरोपी-अपीलकर्ता जरनैल सिंह के साथ थी, और भले ही उसने आरोपी के साथ सहमति से यौन संबंध बनाए हों, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि, नाबालिग की सहमति महत्वहीन है।

18. वर्तमान अपील की सुनवाई के दौरान, अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने विवादित फैसले में उच्च न्यायालय के निर्धारण का जोरदार विरोध किया, जिसमें उसने निष्कर्ष निकाला था कि अभियोजक वी. डब्ल्यू.-पी. डब्ल्यू. 6 नाबालिग था। जहां तक मामले के तत्काल पहलू का संबंध है, यह बताया गया कि अभियोजक वी. डब्ल्यू.-पी. डब्ल्यू. 6 के यौन अंग डॉ. कांता धनखड़ पी. डब्ल्यू. 1 द्वारा पूरी तरह से विकसित पाए गए थे।उसका हाइमेन टूटा हुआ पाया गया। अभियोजक वी. डब्ल्यू.-पी. डब्ल्यू. 6 की चिकित्सकीय-कानूनी जांच का साहस करते हुए यह भी देखा गया कि योनि ने आसानी से दो/तीन उंगलियों को प्रवेश कराया।अपीलार्थी-अभियुक्त जरनैल सिंह के विद्वान वकील ने डॉ. कांता धनखड़-(पीडब्लू1) की जिरह की ओर भी हमारा ध्यान आकर्षित किया, जिसमें उन्होंने अभियोजक द्वारा दिए गए बयान के आधार पर अभियोजक वीडब्ल्यू-पीडब्लू6 की आयु 15 वर्ष के रूप में उल्लेख करने की बात स्वीकार की। डॉ. कांता धनखड़ पीडब्लू1 ने यह भी स्वीकार किया था कि उसने अभियोजक की आयु वैज्ञानिक रूप से निर्धारित करने के लिए अभियोजक वीडब्ल्यू-पीडब्लू6 पर ऑसिफिकेशन परीक्षण नहीं कराया था। उपरोक्त के आधार पर, यह माना गया कि मामले के अभिलेख पर कोई ठोस सामग्री नहीं थी, जिसके आधार पर उच्च न्यायालय द्वारा यह निष्कर्ष निकाला जा सकता था कि अभियोजक घटना की तारीख को नाबालिग था।

19. उसके इस तर्क का समर्थन आदेशने के लिए कि अभियोजक घटना के समय नाबालिग नहीं था, अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने सुनील बनाम हरियाणा राज्य, ए. आई. आर. 2010 एस. सी. 392 में दिए गए फैसले पर भरोसा किया। आम

तौर पर, हम उन टिप्पणियों को निकाल लेते जिन पर निर्भरता रखी गई थी, लेकिन हमारे निष्कर्ष से उभरने वाले कारणों के लिए, हम ऐसा करना अनुचित मानते हैं।

20. नाबालिग की आयु के निर्धारण के मुद्दे पर, केवल किशोर न्यायाधीश (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) नियम, 2007 (इसके बाद 2007 नियम के रूप में संदर्भित) के नियम 12 का संदर्भ देने की आवश्यकता है। वनाच्छादित ई 2007 नियम किशोर न्यायाधीश (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2000 की खंड 68 (1) के तहत बनाए गए हैं।ऊपर उल्लिखित नियम 12 निम्नानुसार हैः

> "12.आयु निर्धारण में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया।(1) कानून के साथ संघर्ष में किसी बच्चे या किशोर से संबंधित प्रत्येक मामले में, अदालत या बोर्ड या जैसा भी मामला हो, इन नियमों के नियम 19 में निर्दिष्ट समिति उस उद्देश्य के लिए आवेदन करने की तारीख से तीस दिनों की अवधि के भीतर कानून के साथ संघर्ष में ऐसे किशोर या बच्चे या किशोर की आयु निर्धारित करेगी।
>
> (2) न्यायालय या बोर्ड या समिति, जैसा भी मामला हो, किशोर या बच्चे या जैसा भी मामला हो, कानून के साथ संघर्ष में किशोर की किशोरता या अन्यथा, प्रथमदृष्टया शारीरिक उपस्थिति या दस्तावेजों के आधार पर निर्णय करेगी।यदि उपलब्ध हो।और उसे ऑब्जर्वेशन होम या जेल भेजें।
>
> (3) कानून के साथ संघर्ष में एक बच्चे या किशोर से संबंधित प्रत्येक मामले में। आयु निर्धारण जांच न्यायालय या बोर्ड या, जैसा भी मामला हो, समिति द्वारा साक्ष्य प्राप्त करके की जाएगी -

(ए) (i) मैट्रिक या समकक्ष प्रमाण पत्र, यदि उपलब्ध हो; और जिसके अभाव में;

((ii) स्कूल से जन्म प्रमाण पत्र की तारीख (एक प्ले स्कूल के अलावा) पहली बार उपस्थित हुई; और जिसके अभाव में;

((iii) किसी निगम या नगरपालिका प्राधिकरण या पंचायत द्वारा दिया गया जन्म प्रमाण पत्रः

(बी) और केवल उपरोक्त खंड (ए) के (i), (ii) या (iii) में से किसी एक की अनुपस्थिति में में, विधिवत गठित चिकित्सा बोर्ड से चिकित्सा राय ली जाएगी, जो किशोर या बच्चे की उम्र घोषित करेगा। यदि आयु का सटीक आकलन नहीं किया जा सकता है, तो न्यायालय या बोर्ड या, जैसा भी मामला हो, समिति, उनके द्वारा दर्ज किए जाने वाले कारणों के लिए, यदि आवश्यक समझा जाए, तो बच्चे या किशोर को एक वर्ष के अंतराल के भीतर कम आयु पर विचार करके लाभ दे सकती है।

और, ऐसे मामले में आदेश पारित करते समय, जो भी मामला हो, उपलब्ध साक्ष्य या चिकित्सा राय पर विचार करने के बाद, उसकी उम्र और खंड (ए) (आई), (बी), (आई) में से किसी में निर्दिष्ट साक्ष्य के संबंध में एक निष्कर्ष दर्ज करेगा या जिसके अभाव में, खंड (बी) कानून के साथ संघर्ष में ऐसे बच्चे या किशोर के संबंध में उम्र का निर्णायक प्रमाण होगा।

(4) यदि अपराध की तारीख को किसी किशोर या बच्चे या कानून के साथ संघर्ष में किशोर की आयु 18 वर्ष से कम पाई जाती है, तो

उपनियम (3) में निर्दिष्ट किसी निर्णायक प्रमाण ए के आधार पर, न्यायालय या बोर्ड या समिति, जैसा भी मामला हो, अधिनियम और इन नियमों के उद्देश्य से आयु और किशोरता की स्थिति या अन्यथा घोषित करने का आदेश लिखित रूप में पारित करेगी और आदेश की एक प्रति ऐसे किशोर या संबंधित बी व्यक्ति को दी जाएगी।

(5) अधिनियम की खंड 7 ए, खंड 64 और इन नियमों के संदर्भ अन्य बातों के साथ साथ आगे की जांच या अन्यथा आवश्यक होने के अलावा, अदालत या बोर्ड द्वारा इस नियम के उप-नियम (3) अन्य बातों के साथ साथ निर्दिष्ट प्रमाण पत्र या किसी अन्य दस्तावेजी प्रमाण की जांच और प्राप्त करने के बाद आगे कोई जांच नहीं की जाएगी।

(6) इस नियम में निहित प्रावधान उन निपटाए गए मामलों पर भी लागू होंगे, जहां उप-नियम (3) और अधिनियम में निहित प्रावधानों के अनुसार किशोरता की स्थिति निर्धारित नहीं की गई है, जिसमें कानून के साथ संघर्ष में किशोर के हित में उचित आदेश पारित करने के लिए अधिनियम के तहत सजा के वितरण की आवश्यकता होती है।

भले ही नियम 12 केवल कानून के साथ टकराव में एक बच्चे की उम्र निर्धारित करने के लिए सख्ती से लागू होता है, हमारा विचार है कि उपरोक्त वैधानिक प्रावधान उम्र निर्धारित करने का आधार होना चाहिए, यहां तक कि एक बच्चे के लिए भी जो अपराध का शिकार है। क्योंकि, हमारे विचार में, जहां तक अल्पसंख्यकों के मुद्दे का संबंध है, कानून के साथ संघर्ष करने वाले बच्चे और अपराध का शिकार होने वाले

बच्चे के बीच शायद ही कोई अंतर है। इसलिए, हमारी सुविचारित राय में, अभियोजक वी. डब्ल्यू.-पी. डब्ल्यू. 6 की आयु निर्धारित करने के लिए 2007 के नियमों के नियम 12 को लागू करना न्यायसंगत और उचित होगा।आयु निर्धारित करने के तरीके को ऊपर निकाले गए नियम 12 के उप-नियम (3) में जी को व्यक्त किया गया है।उपरोक्त प्रावधान के तहत, नियम 12 (3) में प्रतिपादित कई विकल्पों में से पहले उपलब्ध आधार को अपनाकर बच्चे की उम्र का पता लगाया जाता है।यदि नियम 12 (3) के तहत विकल्पों की योजना में, एक विकल्प पूर्ववर्ती खंड में व्यक्त किया जाता है, तो इसका प्रभाव बाद के खंड में व्यक्त विकल्प पर हावी होता है।उपलब्ध उच्चतम मूल्यांकन विकल्प, निश्चित रूप से नाबालिग की आयु निर्धारित करेगा।नियम 12 (3) की योजना में, संबंधित बच्चे का मैट्रिक (या समकक्ष) प्रमाण पत्र, उच्चतम मूल्यांकन विकल्प है।यदि उक्त प्रमाणपत्र उपलब्ध है, तो बी पर किसी अन्य साक्ष्य पर भरोसा नहीं किया जा सकता है।केवल उक्त प्रमाण पत्र की अनुपस्थिति में में, नियम 12 (3), उस स्कूल में दर्ज की गई जन्म तिथि पर विचार करने की परिकल्पना करता है, जिसमें बच्चा पहली बार उपस्थित हुआ था। यदि जन्म तिथि की ऐसी प्रविष्टि उपलब्ध है, तो उसमें दर्शाई गई जन्म तिथि को अंतिम और निर्णायक माना जा सकता है और किसी अन्य सामग्री पर भरोसा नहीं किया जा सकता है।केवल इस तरह की प्रविष्टि की अनुपस्थिति में में, नियम 12 (3) किसी निगम या नगरपालिका प्राधिकरण या पंचायत द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र पर निर्भरता का प्रतिपादन करता है।फिर भी, यदि ऐसा प्रमाण पत्र उपलब्ध है, तो संबंधित बच्चे की उम्र निर्धारित करने के लिए किसी भी अन्य सामग्री पर विचार नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि उक्त प्रमाण पत्र निश्चित रूप से बच्चे की उम्र निर्धारित करेगा।यह केवल उपरोक्त में से किसी की अनुपस्थिति में में है कि नियम 12 (3) चिकित्सा राय के आधार पर संबंधित बच्चे की उम्र का निर्धारण करता है।

21. 2007 के नियमों के नियम 12 की योजना का पालन करते हुए, यह स्पष्ट है कि अभियोजक वी. डब्ल्यू.-पी. डब्ल्यू. 6 की आयु मैट्रिक (या समकक्ष) प्रमाण पत्र के आधार पर निर्धारित नहीं की जा सकी क्योंकि उसने खुद को अपदस्थ कर दिया था, कि उसने केवल कक्षा 3 तक की पढ़ाई की थी, और उसके बाद, उसने अपना स्कूल छोड़ दिया था और एफ ने घरेलू काम करना शुरू कर दिया था।इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में अभियोजन पक्ष ने 2007 के नियमों के नियम 12 (3) में व्यक्त विकल्पों के क्रम में, अगले उपलब्ध आधार पर अभियोजन पक्ष वी. डब्ल्यू.-पी. डब्ल्यू. 6 की आयु स्थापित करने का प्रयास किया था।अभियोजन पक्ष ने अभियोजक वी. डब्ल्यू.-पी. डब्ल्यू. 6 की जी आयु को साबित करने के लिए सतपाल (पी. डब्ल्यू. 4) को पेश किया।सतपाल (पीडब्लू 4) गवर्नमेंट हाई स्कूल, जथलाना के हेडमास्टर थे, जहाँ अभियोजक वीडब्ल्यू-पीडब्लू 6 ने कक्षा 3 तक पढ़ाई की थी।सतपाल (पीडब्लू4) ने प्रमाण पत्र प्रदर्शनी-पीजी को साबित कर दिया था, जैसा कि स्कूल के रिकॉर्ड के आधार पर बनाया गया था, जो दर्शाता है कि अभियोजक वीडब्ल्यू-पीडब्लू6 का जन्म 15.5.1977 पर हुआ था।2007 के नियमों के नियम 12 (3) के तहत विचार की गई योजना में, किसी अन्य तरीके से आयु निर्धारित करने की अनुमति नहीं है, और निश्चित रूप से बाद के खंड में उल्लिखित विकल्प के आधार पर नहीं।इसलिए हमारा विचार है कि उच्च न्यायालय अभियोजक वी. डब्ल्यू.-पी. डब्ल्यू. 6 की आयु स्थापित करने के लिए उपरोक्त आधार पर भरोसा करना पूरी तरह से उचित था।यह उल्लेख करना भी प्रासंगिक होगा कि 2007 के नियमों के नियम 12 की योजना के तहत, उच्च न्यायालय के लिए अभियोजक वी. डब्ल्यू.-पी. डब्ल्यू. 6 की आयु निर्धारित करने के लिए अस्थिकरण परीक्षण सहित किसी अन्य सामग्री पर भरोसा करना अनुचित होता। सतपाल-पीडब्लू4 के बयान का विरोध नहीं किया गया है।इसलिए, अभियोजक वी. डब्ल्यू.-पी. डब्ल्यू. 6 (प्रदर्शनी पी. जी. में इंगित, 15.7.1977 के रूप में) की जन्म

तिथि अंतिम मानी जाती है।तदनुसार यह स्पष्ट है कि अभियोजक वी. डब्ल्यू.-पी. डब्ल्यू. 6, घटना की तारीख को 15 वर्ष से कम उम्र का था, यानी 25.3.1993 पर। मामले के उक्त दृष्टिकोण में, इस बात में कोई संदेह नहीं है कि अभियोजक वी. डब्ल्यू.-पी. डब्ल्यू. 6 घटना की तारीख को नाबालिग था। तदनुसार, हम एतद्द्वारा उच्च न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्षों का समर्थन करते हैं, कि भले ही अभियोजक वी. डब्ल्यू.-पी. डब्ल्यू. 6 ने अभियुक्त अपीलकर्ता जरनैल सिंह के साथ अपनी स्वतंत्र इच्छा से यौन संबंध बनाए हों, और उसके साथ सहमति से यौन संबंध बनाए हों, लेकिन यह स्पष्ट रूप से अप्रासंगिक होता, क्योंकि वह नाबालिग थी।

22. चूँकि अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जिस निर्णय पर भरोसा किया गया है, वह तथ्यों के आधार पर अलग-अलग है।और चूंकि निर्णय पर भरोसा किया गया था, 2007 के नियमों का कोई संदर्भ नहीं दिया गया था, इसलिए हमारा विचार है कि अभियोजक वी. डब्ल्यू.-पी. डब्ल्यू. 6 की आयु निर्धारित करने के उद्देश्यों के लिए यह प्रासंगिक एफ नहीं होगा, विशेष रूप से सतपाल (पी. डब्ल्यू. 4) द्वारा से अभियोजन पक्ष के नेतृत्व में साक्ष्य की पृष्ठभूमि में।

23. अभियुक्त-अपीलार्थी जरनैल सिंह के विद्वान अधिवक्ता के हाथों अगला तर्क यह था कि अभियोजक वी. डब्ल्यू.-पी. डब्ल्यू. 6 की मौखिक गवाही को अभियुक्त-अपीलार्थी जरनैल सिंह के खिलाफ अपराध का निष्कर्ष देने के लिए पर्याप्त नहीं माना जाना चाहिए। जहाँ तक अभियोजक वी. डब्ल्यू.-पी. डब्ल्यू. 6 की गवाही का संबंध है, यह इंगित किया जाता है कि इसमें कई विसंगतियाँ और विरोधाभास थे। यह प्रस्तुत किया गया था कि इस तरह की विसंगतियों को निचली अदालत के समक्ष उसके बयान की तुलना, 6.4.1993 पर आपराधिक प्रक्रिया संहिता की खंड 164 के तहत दर्ज अभियोजक के बयान के साथ, और साथ ही, 29.3.1993 पर आपराधिक प्रक्रिया संहिता

की खंड 161 के तहत जांच अधिकारी द्वारा दर्ज अभियोजक के बयान के साथ देखा जा सकता है।

24. हमने अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता के हाथों दिए गए उपरोक्त उल्लिखित निवेदन पर विचारपूर्वक विचार किया है। हालाँकि, हम इसमें कोई योग्यता नहीं पाते हैं। ऐसा नहीं है कि अभियोजन पक्ष का बयान पूरी तरह से अभियोजक वी. डब्ल्यू.-पी. डब्ल्यू. 6 के बयान पर आधारित है। यह उल्लेख करना प्रासंगिक होगा कि रायपुर में शशि भान के घर से आरोपी अपीलकर्ता जरनैल सिंह की हिरासत से उसकी बरामदगी मोती राम-पीडब्लू 3 के बयान से स्थापित की जानी चाहिए। इसलिए इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि जब वह अपने पिता के आवास से 25.3.1993 पर लापता पाई गई थी, और उसके पिता जगदीश चंद्र-पीडब्लू8 द्वारा 27.3.1993 पर पुलिस में शिकायत करने के बाद, उसे आरोपी-अपीलकर्ता जरनैल सिंह की हिरासत से बरामद कर लिया गया था।इसके बाद, अभियोजक वी. डब्ल्यू.-पी. डब्ल्यू. 6 की डॉ. कांता धनखड़-पी. डब्ल्यू. 1 द्वारा दोपहर 3 बजे चिकित्सा-कानूनी जांच की गई। डॉ. कांता धनखड़-पी. डब्ल्यू. 1 ने अपनी स्वतंत्र गवाही में पुष्टि की कि उसे यौन संभोग के लिए एफ के अधीन किया गया था, क्योंकि उसका हाइमेन फट गया था। भले ही अभियोजक वी. डब्ल्यू.-पी. डब्ल्यू. 6 की दृश्य जांच, उसकी चिकित्सा-कानूनी जांच के दौरान वीर्य या रक्त की उपस्थिति का खुलासा नहीं करती थी, फिर भी फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला (एक्सहिबिट पी. एल.) और सीरोलॉजिस्ट (एक्सहिबिट पी. एल./1) की रिपोर्ट स्पष्ट रूप से उसके सलवार, अंडरवियर और प्यूबिक बालों पर वीर्य की उपस्थिति स्थापित करती है। सीरोलॉजिस्ट की रिपोर्ट से उनके "सलवार" पर मध्यम और छोटे रक्त के धब्बों का भी पता चलता है।अपने स्वयं के बयान में, उसने उल्लेख किया था कि जब आरोपी-अपीलार्थी जरनैल सिंह और उसके साथियों द्वारा उसके साथ बलात्कार किया गया था, तो खून बह रहा था और उसे दर्द हो रहा था, और उसके कपड़े खून से सना हुए थे।

उनका निक्षेपण प्रदर्शनी पी. एल. और पी. एल./1 द्वारा वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित है। अभियुक्त-अपीलार्थी जरनैल सिंह के कहने पर अभियोजक वी. डब्ल्यू.-पी. डब्ल्यू. 6 को उसकी जिरह के दौरान यह सुझाव दिया गया कि वह अभियुक्त-अपीलार्थी जरनैल सिंह के साथ अपनी मर्जी से गई थी और उसने सहमति से उसके साथ यौन संबंध बनाए थे, इस बात में कोई संदेह नहीं है कि वह उसके साथ थी और उसने उसके साथ यौन संबंध बनाए थे।यह दावा कि अभियोजक वी. डब्ल्यू.-पी. डब्ल्यू. 6 अभियुक्त अपीलार्थी जरनैल सिंह के साथ था, और उसके साथ सहमति से यौन संबंध बनाए थे, पूरी तरह से खारिज कर दिया गया है, क्योंकि अभियोजन पक्ष के प्रमाणित संस्करण के अनुसार, अभियोजक वी. डब्ल्यू.-पी. डब्ल्यू. 6 को अकेले अभियुक्त-अपीलार्थी जरनैल सिंह द्वारा नहीं, बल्कि उसके तीन सहयोगियों द्वारा भी ले जाया गया था। उन चारों ने समान रूप से उसके व्यक्तित्व का उल्लंघन किया था। इसके अतिरिक्त, दंड प्रक्रिया संहिता की खंड 164 के तहत अपने बयान में, अभियोजक वी. डब्ल्यू.-पी. डब्ल्यू. 6 ने दावा किया था कि पहली बार में, उसे पकड़ने के बाद, आरोपी ने उसे एक कपड़े से कुछ सांस लेने के लिए कहा था जिससे वह बेहोश हो गई थी।इसके बाद, जब आरोपी-अपीलकर्ता जरनैल सिंह ने उसके साथ संभोग करने का प्रयास किया, तो उसने उसे थप्पड़ मार दिया था। फिर उसने उसके मुँह में एक कपड़ा डाल दिया था, ताकि वह उसे शोर मचाने से रोक सके।इसके बाद, प्रत्येक साथी ने बारी-बारी से उसके साथ जबरन यौन संबंध बनाए। अभियुक्त-अपीलार्थी और उसके सहयोगियों द्वारा जबरन संभोग करने के तथ्य को उसने निचली अदालत के समक्ष पी. डब्ल्यू. 6 के रूप में अपनी गवाही के दौरान दोहराया था।उपरोक्त के अलावा, उसके अपने पिता, जगदीश चंद्र (पीडब्लू8) का एक बयान है, जिन्होंने भौतिक विवरणों में भी अभियोजक वीडब्ल्यू-पीडब्लू6 की गवाही की पुष्टि की थी।अभियोजक वी. डब्ल्यू.-पी. डब्ल्यू. 6, से इनमें से किसी भी मुद्दे पर जिरह नहीं की गई थी।न ही अभियोजक जी को आपराधिक अभियोजन संहिता की खंड 161 या खंड

164 के तहत उसके द्वारा दिए गए बयानों का सामना करना पड़ा, ताकि वह विसंगतियों, यदि कोई हो, को समझाने में सक्षम हो सके।इसलिए, हम विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रस्तुति में कोई योग्यता नहीं पाते हैं।मामले के उपरोक्त दृष्टिकोण में, हम संतुष्ट हैं कि अभियुक्त अपीलकर्ता जरनैल सिंह के अपराध के स्पष्ट निर्धारण के लिए अभियोजक वी. डब्ल्यू.-पी. डब्ल्यू. 6 के बयान की पुष्टि करने वाली पर्याप्त सामग्री थी।

25. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता के हाथों उपरोक्त मामलों के अलावा कोई अन्य निवेदन आगे नहीं बढ़ाया गया था।ऊपर दर्ज किए गए कारणों से, हम तत्काल अपील में कोई योग्यता नहीं पाते हैं और तदनुसार इसे खारिज कर दिया जाता है।

बी. बी. बी. अपील खारिज।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल सुवास की सहायता से अनुवादक द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण : यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिये स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उददेश्य के लिये इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उददेश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उददेश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।